

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
27.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 15.00 बजे

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में माइनिंग पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक नीरज नैय्यर के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इस बदलाव के लिए सभी तथ्यों और मामलों का अध्ययन करेगी और जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान माइनिंग रूल्स 1971 से लागू हैं, जिनमें 2015 में कुछ संशोधन किए गए थे। इससे पहले विधायक डॉक्टर जनक राज के मूल सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि माइनिंग पॉलिसी के तहत चंबा जिला की सलूणी तहसील में सयूल खड्ड के किनारे तलोड़ी में एक खनन पट्टा व उसके आसपास कंडला और मोहड़ी में एक-एक खनन पट्टा मंजूर किया गया है। उद्योग मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन खनन पट्टों को प्रदान करते समय माइनिंग पॉलिसी व नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एम.बी.बी.एस. डिग्री कर चुके करीब दो हजार डिग्री धारक डॉक्टर बेरोजगार हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों से हर साल एम.बी.बी.एस. पास होकर निकलते हैं, जिससे बेरोजगार डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डॉक्टरों के लिए बांड सिस्टम को जरूरी कर दिया है, ताकि वे प्रदेश में काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को एक साल के भीतर बेहतर किया जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला के तपोवन में देश का सबसे बड़ा और भव्य इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसके निर्माण के लिए जगह को चिन्हित कर लिया गया है और यह प्रोजेक्ट एशियाई विकास बैंक की सहायता से पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में ए.डी.बी. के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कुल 8 सौ 44 करोड़ 15 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त ए.डी.बी. के पास दायर 7 सौ 9 करोड़ 90 लाख रुपये के प्रतिपूर्ति दावों के मुकाबले प्रदेश को 6 सौ 77 करोड़ 69 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि ए.डी.बी. की परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और इन प्रमाण पत्रों के जारी होने के बाद ही भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति दावों के विरुद्ध प्रदेश सरकार को धनराशि जारी की जाती है।

भाजपा प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में राज्य सरकार के कथित जनविरोधी नीतियों, कुशासन और माफिया राज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सहप्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के अढ़ाई वर्षों के कुशासन ने प्रदेश को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल 4 महीने में प्रदेश को 32 हजार करोड़ रुपये के नए कर्ज के बोझ तले दबा दिया है।

इस मौके पर प्रदेश भाजपा सहप्रभारी संजय टंडन ने कहा कि हिमाचल में जंगलराज हावी हो चुका है और चिट्ठा माफिया युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार महिला विरोधी सरकार साबित हो चुकी है और माताओं-बहनों को प्रतिमाह 15 सौ रुपये देने की झूठी गारंटी देकर उनके साथ धोखा किया गया है। संजय टंडन ने कहा कि सुक्खू सरकार में हिमाचल गैंग वॉर का केन्द्र बन चुका है और अपराधी बेखौफ होकर दिनदहाड़े गोलियां चला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रदेश से माफिया राज को खत्म किया जाए और भाजपा का कुशासन और अराजकता के खिलाफ ये प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस के पतन की शुरुआत है। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

.....